श्री मोहम्मद अफजल उर्फ **मीम अफजल** : ठाकुर साहब को मालूम नहीं है, मनमोहन सिंह जी जवाब क्यों नहीं देते हैं ?

श्री सभापति : आप जगेश देसाई जी के प्रश्न का उत्तर दे दीजिए । वह कहते हैं क्या आप गाइडलाइंस को बदलने का विचार कर रहे हैं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : जी हां, गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रहे हैं ।

*204. [*The questioners (Kumari Sayeeda Khatun and Shri Bhuvanesh Chaturvedi) were absent; For answer, vide Cols.* 40-41 Infra]

Development of Non-Conventional Energy Sources in Rajasthan

*205. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state :

(a) whether the Central Government have not so far decided upon any action plan for the development of non-conventional energy sources in Rajasthan resulting in Rajasthan being continuously dependent on partnership power generation projects in the Central Sector with the adjoining States ; and

(b) if so, what are the details of each such project including the number of non-conventional energy projects proposed to be launched during the Eighth Five Year Plan period in Rajasthan ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) *A Statement is laid on the Table of the* House.

Statement

(a) Government is implementing nation-wide programme on non-conventional energy sources including in the State of Rajasthan. It is proposed to continue with the implementation of various programmes during the year 1992-93 and the 8th Five Year Plan (1992—97). The state Government of Rajasthan has an approved outlay of Rs. 3.25 crores for the Annual Plan (1992-93). Installation of non-conventional energy systems and devices proposed to be taken up by the State of Rajasthan during the year 1992-93 is given in attached statement I (*See* below).

The Central Government Department (Dept. of Non-conventional Energy Sources) also extends financial assistance to State Govts./Nodal Agencies in the States for implementation of various programmes. as per its approved country-wide pattern, in addition to the State outlays for the different programmes, for demonstration, research and development, and extension of non-conventional energy sources. The cumulative achievement of installation of various systems and devices in the State of Rajasthan up to 31-3-1992, is as at Statement II (*See* below).

Power requirements of Rajasthan are met besides its own generation from several other shares/Joint Projects as well as Central Projects in which Rajasthan has share.

However, the non-conventional energy sources can meet/supplement only part of the energy requirements in some of the sectors, like cooking and heating through biogas plants, Improved Chulhas, Solar water heating systems, Solar distillation systems and Solar cookers, The contribution of non-conventional energy sources in terms of electrical power so far has been rather small. The electricity needs on decentralised basis can be met through the installation of non-conventional energy systems and devices based on solar photovoltaic, wind, biomass and small hydel energy to some extent.

(b) The proposals for 8th Five Year Plan have not yet been finalised.

Statement-I

Installation of Non Conventional Energy Systems & Devices Proposed To Be Taken Up By The State Of Rajasthan During The Year 1992-93

S. No.	Systems/Devices	Proposed physical targets
1	Family type biogas plant	2,500 Nos.
2	Improved Chulha	1.25 lakh
3	Solar water heating systems (Litres per day)	13,350
4	Solar Cookers	4,500 Nos.
5	Solar photovoltaic street lights (Recommissioning)	728 Nos.
6	Photovoltaic Power unit	1 No. (50 Kwp)
7	Wind pumps	5 Nos.
8	Integrated Rural Energy Programme	7 Blocks.

Statement-II

Status Of Implementation Of Non-Conventional Energy Systems & Devices In The State Of Rajasthan

S. No.	Programme	Units	*Cumulativ achievemen (Up to) (31-3-199
1	National Project on Biogas Development (Family size biogas plants)	Nos.	42,550
2	Community/Institutional Biogas plants.	Nos.	35
3	National Programme on Improved Chulhas	Nos. in lakh	12.25
4	Industrial Solar Water Heating Systems	Ltrs. per day in lakh.	1.08
5	Solar cookers	Nos.	25,389
6	Villages provided with photovoltaic street lights	Nos.	707
7	Photovoltaic water pumps	Nos.	86
8	Photovoltaic Community lights/TV and community facilities	Nos.	110
9	Photovoltaic Power pack	No.	1(10 Kwp
10	Wind Pumps	Nos.	112
11	Deep Well Wind Pumps	Nos.	16
12	Wind Battery chargers	Nos.	9
13	Mini-Micro Hydro	MW	0.97(4.76)
14	Urjagram Projects	Nos.	1(25)
15	Biomass Energy Plantations (Sanctioned)	Hectares	146(
16	Biomass Gasifiers/Stirling Engines	Nos.	1(

*Achievement figures for the year 1991-92 are yet to be firmed up.
( ) Projects under installation.

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता था विशेष रूप से उनको इस बात का आभास है कि जो मेरा प्रश्न है राजस्थान के सन्दर्भ में है। राजस्थान में मरूस्थल होने की वजह से वर्ष में 300 दिन काफी गर्मी पड़ती है और तेज हवाएं चलती हैं, पशु-धन भी वहां बहुत है, गोबर भी काफी पैदा होता है। इसलिए वहां पर गैर-पारम्परिक ऊर्जा के स्रोतों के विकास का काफी स्कोप है। मंत्री महोदय ने जो यह उत्तर दिया है, काफी विस्तृत उत्तर देने का प्रयत्न किया है। लेकिन मुख्य प्रश्न रह गया है जिसका उत्तर उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया है, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने आपको जोधपुर में मथानिया में एक सोलर ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने के लिए योजना भेजी थी। वह योजना 1989 में भेजी गई थी। उस समय उसकी लागत 90 करोड़ रुपये की थी। लेकिन आपके विचार-विनिमय के अन्दर इतना विलम्ब हो गया है कि 1991 में वह योजना 180 करोड़ रुपये की हो गई और 1992 में न जाने उस योजना में कितना पैसा लगेगा। इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने आपको सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करा दीं, सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध करा दी तथा राजस्थान ने अपने हिस्से का 32 करोड़ रुपया देना भी स्वीकार कर लिया, इसके बावजूद भी मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि मंत्री महोदय कृपा करके यह बताएं कि सौर ऊर्जा का जो स्टेशन लगने वाला था उसको आप कब स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, यदि नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके कुछ कारण दिये जाने चाहिएं ?

श्री कल्पनाथ राय : सभापति जी, भारत सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्देशन में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अपने देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस विभाग को प्राथमिकता दी थी। माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि जोधपुर के पास 30 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जो सौर ऊर्जा पर आधारित होगा उसके संबंध में भारत सरकार क्या कर रही है। सन् 1988-89 में जोधपुर के पास सौर ऊर्जा पर आधारित एक पावर प्लांट बनाने का राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया था। भारत सरकार ने उस प्रस्ताव पर विचार किया। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी के पास वह प्रस्ताव भेजा गया। सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी ने उस पर यह सिफारिश की कि चूंकि 7 करोड़ रु० प्रति मेगावाट बिजली इससे बनेगी इसलिए यह बहुत मंहगा है। इसलिए टेक्नो-इक्नामिकली यह कामर्शियल नहीं है एवं इसको भारत सरकार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। परन्तु इसके बावजूद भी भारत सरकार से वहां के मुख्य मंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत जी ने निवेदन किया कि चूंकि राजस्थान में सौर ऊर्जा की उपलब्धता सबसे ज्यादा है और कैलीफोर्निया में 30 से 80 मैगावाट के सौर ऊर्जा पर आधारित बिजली स्टेशन बन चुके हैं (कुल 350 मेगावाट) इसलिए आप जो भी हमसे कहेंगे हमारी सरकार उस पर विचार करेगी। भारत सरकार श्री भैरों सिंह शेखावत के इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और पुन: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी से परीक्षण कराया जा रहा है कि समुचित क्षमता के सौर स्टेशन की इक्नामिक वायेबिलिटी को निकालें और इस प्रोजेक्ट को रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के रूप में स्वीकार करने पर विचार करें ताकि हिंदुस्तान में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली को पैदा किया जा सके।

श्री राम दास अग्रवाल : महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि 7 करोड़ रुपया पर मेगावाट उसकी इंस्टालेशन कास्ट आयेगी। लेकिन जिस समय यह प्लान बनाया गया था उस समय

केवल वह 3 करोड़ रुपये था। आप लोगों के विलम्ब के कारण, निर्णय न लेने की क्षमता के कारण ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं और धीरे धीरे उसका इंस्टालेशन कास्ट बढ़ता जा रहा है। इसमें न ही हमारी राजस्थान सरकार का दोष है और न ही प्रकृति का दोष है, यह केवल आपके निर्णय न लेने की जो क्षमता है उसका दोष है। आप उसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने क्या इस बात का अंदाज किया है, एनेलिसिस और असेसमेंट किया है कि 7 करोड़ रुपया पर मेगावाट इसकी इंस्टालेशन कास्ट आने के बाद भी इसकी उत्पादन कास्ट कितनी आएगी। ऊर्जा की कास्ट आज जो हम थर्मल या हाइडिल से लेते हैं वह डेढ़ रुपये से दो रुपये पर यूनिट आती है क्या इससे भी ज्यादा इसकी कास्ट आएगी यह कृपा करके बताएं।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, मैंने आदरणीय अग्रवाल जी से निवेदन किया कि यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी के पास में संशलेषण और विश्लेषण के लिये भेजा है... (**व्यवधान**)

श्री रामदास अग्रवाल : तीन साल में 90 करोड़ से 200 करोड़ रुपये उसकी कास्ट हो गयी है। अगर दो साल के बाद हम बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसकी इंस्टालेशन कास्ट... (**व्यवधान**) 16 करोड़ पर मेगावाट आयेगी। आज जल्दी क्यों नहीं करते। निर्णय लेकर जल्दी हां या ना का जवाब दीजिए... (**व्यवधान**) इसको खिले कर रहे हैं।

श्री सभापति : पहले उन्होंने ना किया था। फिर जब मुख्य मंत्री ने कहा फिर से विचार कीजिए तो फिर विचार कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को पुनः संशलेषण विश्लेषण के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी को भेज दिया गया है। उसके बाद आवश्यकतानुसार पी०आई०बी०, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड में जाएगा। जब तक इसका टेक्नो इक्नामिकल क्लीयरेंस नहीं होगा तब तक भारत सरकार इसमें सहमति नहीं देगी... (**व्यवधान**) इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थर्मल से ज्यादा पड़ेगी ... (**व्यवधान**)... इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक टेक्नोइक्नामिक क्लीयरेंस नहीं हो जाएगा तब तक भारत सरकार का एप्रुवल इस पर नहीं हो सकता। फिर भी आपके शेखावत जी के अनुरोध पर यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और हम कोशिश करेंगे... (**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल मैं कास्ट आफ प्रोडक्शन पूछ रहा हूं कि थर्मल और सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन करने में कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आएगी। पर यूनिट क्या कास्ट आती है। आपने 7 करोड़ रुपया पर मेगावाट इंस्टालेशन कास्ट में लगा दिया लेकिन प्रोडक्शन कास्ट क्या आएगी यह तो बता दीजिए कृपा करके।

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय, अग्रवाल जी से मैंने निवेदन किया कि इसका टेक्नो-इक्नामिक कामर्शियल संशलेषण हो रहा है। इसके बाद ही मैं आपको बता पाउंगा।

श्री सभापति : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Retaliatory Trade Action Against India Under Special 301

*204. KUMARI SAYEEDA KHATUN :
SHRI BHUVNESH CHATURVEDI :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the US Administration have announced retaliatory trade action against India under the Special 301, withdrawing